हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 05 अंक 29 | लखनऊ शनिवार 25 जुलाई 2026 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा- नए पात्र अभ्यर्थियों को भी भर्ती करेंगे

67 हजार शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी

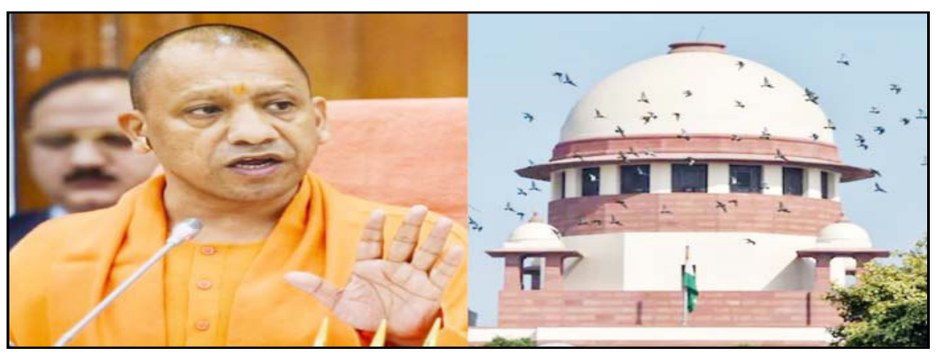

नई दिल्ली/लखनऊ संवाददाता। यूपी सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। सरकार ने बताया- 2020 में नियुक्त 67 हजार 867 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट में कुछ नए कैंडिडेट पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें खाली पड़े पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ने सुबह करीब 11 बजे कोर्ट से यह भी कहा कि यह फैसला सिर्फ 69 हजार शिक्षक भर्ती के इस मामले तक सीमित रहेगा। इसे भविष्य की किसी दूसरी भर्ती के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 9 हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो अपनी पात्रता का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सरकार ने कहा है कि इन्हें नियमों के तहत नौकरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर यूपी में अभ्यर्थियों ने कई बार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2019 में बेसिक शिक्षा परिषद ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाई थी। इसका नोटिफिकेशन 2018 में जारी हुआ था। इसी भर्ती में ओबीसी कैटेगरी में टोटल 18,598 सीटें थीं, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स को सिर्फ 2,637 सीटें ही दी गईं।आरोप है कि ओबीसी को 27प्रतिशत की जगह सिर्फ 3.86प्रतिशत ही रिजर्वेशन दिया गया। इसी तरह से स्ट कैंडिडेट्स को 21प्रतिशत की जगह 16.6प्रतिशत ही आरक्षण मिला। इस भर्ती में बेसिक एजुकेशन रूल 1981 और रिजर्वेशन रूल 1994 का उल्लंघन किया गया है। आरक्षित वर्ग की सीटें दूसरों को दी गई हैं। जबकि सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नियमावली के तहत कराई गई है।69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 6 जनवरी, 2019 को एटीआरई 2019 परीक्षा हुई। फिर 7 जनवरी 2019 को सरकार ने जनरल कैटेगरी के लिए 65प्रतिशत और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60प्रतिशत न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय किए।

6800 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट भी फंसी

- सरकार ने बताया कि 5 जनवरी 2022 को 6800 कैंडिडेट्स की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन 27 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। बाद में 15 मार्च 2022 को विशेष अपील में भी यह रोक जारी रही। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के अलग-अलग फैसले 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि जिन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने 60 से ज्यादा लेकिन 65प्रतिशत से कम नंबर हासिल किए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट्स की नियुक्ति सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की सीटों पर ही होगी। कोर्ट ने 1 जून 2020 की सिलेक्शन लिस्ट में संशोधन करने और 5 जनवरी 2022 की दूसरी लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही सरकार को यह भी छूट दी कि अगर जरूरत पड़े तो बाहर होने वाले शिक्षकों के लिए अलग नीति बना सकती है। इसके खिलाफ दायर अपीलों पर 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला रद्द कर दिया।

लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक-2026 पेश

पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित नकल और अन्य अनियमितताओं पर सख्ती बढ़ाने के लिए सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है। सरकार के अनुसार, हाल के वर्षों में प्रश्नपत्र लीक और संगठित परीक्षा घोटालों की घटनाओं को देखते हुए वर्ष 2024 में बने कानून को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा को और कड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसे मामलों में न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में परीक्षा आयोजित करने वाली सेवा प्रदाता एजेंसियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है। यदि कोई एजेंसी परीक्षा में धांधली या पेपर लीक में शामिल पाई जाती है तो उस पर अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही ऐसी एजेंसी को सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने से चार वर्ष के बजाय आठ वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा। सेवा प्रदाता संस्थाओं के प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष की कैद तथा अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। संगठित तरीके से परीक्षा संबंधी अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा सात वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक होगी, जबकि अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक लगाया जा सकेगा। विधेयक में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार को ऐसे मामलों की जांच विशेष कार्यबल (स्पेशल टास्क फोर्स) को सौंपने का अधिकार होगा। जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में होगी और मुकदमे का निपटारा तीन महीने के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक विशेष अदालत के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी और यथासंभव उसका निपटारा तीन महीने के भीतर किया जाएगा। गौरतलब है कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 21 जून 2024 से लागू है। यह कानून संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तथा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौतायोग्य हैं।

संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटा

➤ संसद के मौजूदा सत्र की शुरुआत से जारी गतिरोध अब टूट गया है। विपक्षी सदस्य प्रश्नपत्र लीक की रोकथाम लगाने वाले विधेयक पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर प्रमुख राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स ने सदन में इस विधेयक पर चर्चा के लिए सहमति जता दी है। सूत्रों ने बताया कि संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक- 2026 पर गतिरोध समाप्त हो गया है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मंगलवार से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। सदन की कार्यवाही के दौरान ओम बिरला ने सभी दलों से आग्रह किया था कि यह विषय देश के करोड़ों विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस पर व्यापक और सार्थक चर्चा होना उचित है। अध्यक्ष की इस सकारात्मक पहल के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से लोकसभा अध्यक्ष ने स्वयं बातचीत की।

नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट

अररिया प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी

अररिया, एजेंसी। नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प और सांप्रदायिक तनाव के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घटना में 24 वर्षीय बोलबम श्रद्धालु ओमप्रकाश मेहता की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद सीमावर्ती बिहार के अररिया जिले में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अररिया के जिलाधिकारी (डीएम) विनोद दूहन और पुलिस अधीक्षक (एसपी) जितेन्द्र कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। दोनों अधिकारियों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) राजकिशोर कुमार के साथ फुलकाहा और घूरना थाना क्षेत्रों से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा का गहन निरीक्षण किया तथा सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मानिकपुर, कोशिकापुर समेत कई सीमावर्ती गांवों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नेपाल की घटना का किसी भी प्रकार का प्रभाव भारतीय क्षेत्र में नहीं पड़ने दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) की 56वीं और 52वीं बटालियन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सीमा पर चौकसी और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। भारत-नेपाल सीमा से आने-जाने वाले प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की सघन जांच की जा रही है। सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल और एसएसबी के जवानों की तैनाती कर संयुक्त गश्त तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने सीमावर्ती गांवों में ग्रामीणों के साथ बैठक कर शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्व की जानकारी तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को देने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।

प्रदर्शन पर लाठीचार्ज सही नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लाठीचार्ज पर एससी का सख्त रुख, सरकारों को दिया अहम संदेश

नयी दिल्ली एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान प्रदत्त है और किसी आंदोलन का हवाला देकर पुलिस की ज्यादतियों या लाठीचार्ज को उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें देश भर में नीट प्रश्नपत्र लीक और अन्य परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफपुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा पीठ विरोध-प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था, उनके कुछ परिवार के सदस्यों की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करने को तैयार हो गई। इस याचिका पर दूसरी सूचीबद्ध याचिकाओं के साथ ही सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान प्रदत्त अधिकार है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। केवल यह कहकर कि आंदोलन चल रहा है, पुलिस की ज्यादतियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जब एक वकील ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, तो पीठ ने कहा, हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो। पीठ ने कहा, इसके लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रदर्शन के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और अनावश्यक पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए। यदि कुछ असामाजिक तत्व हों, तो उनसे कानून के अनुसार से निपटा जा सकता है। यह केवल दिल्ली का मामला नहीं है। पूरे देश में एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई आंदोलन हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि लाठीचार्ज किया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि लोग स्वयं अनुशासन का पालन करें।श्श् उन्होंने पक्षकारों से पीठ की सहायता करने का भी आग्रह किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस मामले में निष्पक्ष रूप से अदालत की सहायता करेंगे। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अधिवक्ता फौजिया शकील ने आरोप लगाया कि बिहार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफपुलिस ने एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि बिहार में छात्रों पर हमले की कई घटनाएं भी हुई हैं।

नीट केस- फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन सुनवाई टली

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को पहले ही दिन सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान ष्टक्चढ्ढ की ओर से कोई सरकारी वकील मौजूद नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सीबीआई का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 अगस्त तक टाल दी। आरोपियों की ओर से वकील एपी सिंह पेश हुए थे। यह पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत बनी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई थी।

अब ह्श्वश्वञ्ज पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इसी कोर्ट में होगी।

'पेपर लीक बिल' पर चर्चा न होने देना दुर्भाग्यपूर्ण: रिजिजू

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देशभर के छात्रों की मांगों और हाल में हुए छात्र आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सरकार परीक्षा में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यदि इतने बड़े छात्र आंदोलन के बाद भी इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो पाती, तो यह न संसद के लिए अच्छा है और न ही लोकतंत्र के लिए। ससंद बहस और चर्चा का सर्वोच्च मंच है, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर यहीं सार्थक चर्चा होनी चाहिए। रिजिजू ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं तथा नारेबाजी, काले कार्ड दिखाकर और अन्य तरीकों से सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों से अपील की कि वे देश के छात्रों की भावनाओं को समझें और हंगामा करने के बजाय इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा निर्णय लिया है और इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक पेपर लीक रोकने के लिए सख्त और समयबद्ध प्रावधानों के साथ-साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है, जिससे छात्रों का भविष्य अधिक सुरक्षित होगा। उन्होंने सभी दलों से छात्रों के हित को सर्वोपरि रखते हुए विधेयक पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा करने की अपील की

सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के छात्र आंदोलन के दौरान अनशरत रहे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल से सोमवार को छुट्टी मिल गई। यह जानकारी वांगचुक ने खुद एक्स पर साझा एक वीडियो में दी। वांगचुक ने कहा, ÷मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाऊंगा और फिर पहाड़ों की ओर लौट जाऊंगा। उन्होंने मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम के डॉक्टरों और स्टाफ की टीम का आभार भी जताया। उल्लेखनीय है कि वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 37 दिनों तक चले सीजेपी के छात्र आंदोलन के दौरान 26 दिनों तक अनशन रखा था। इसी बीच अस्वस्थ होने के कारण उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से आज उनको छुट्टी मिल गई।

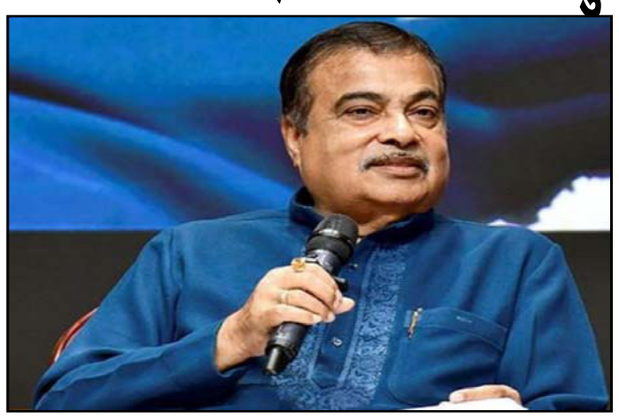

देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत समन्वय : गडकरी

हरिद्वार,एजेंसी। देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज में सोमवार को 46वां ज्ञान दीक्षा संस्कार समारोह उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ। समारोह में बिहार, गुजरात, उत्तराखण्ड, उप्र, मप्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों व देशों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भारतीय ऋषि परंपरा में शिक्षा को श्रेष्ठता के जागरण का मार्ग माना गया है। आत्म उन्नति, चरित्र निर्माण और लोकमंगल की भावना का विकास ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत समन्वय है। यहां योग,यज्ञ,साधना,भारतीय जीवन शैली,पर्यावरण संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानार्जन के साथ उच्च जीवन-दृष्टि अपनाकर हम स्वयं के साथ देश को भी प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने कहा कि ज्ञान दीक्षा हमें स्मरण कराती है कि जीवन में कुछ अच्छा,बड़ा और सार्थक करने के लिए दृढ़ संकल्प ही पर्याप्त है। ऐसे में युवाओं को अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानकर उनका सकारात्मक विकास करना चाहिए। यह समय ज्योति से ज्वाला बनकर राष्ट्र और समाज के नव निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का है। शांतिकुंज प्रमुख व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ.प्रणव पण्ड्या ने नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ज्ञान दीक्षा प्रदान की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों,सेवा-भावना एवं भारतीय संस्कृति के आदर्शों का बोध कराया गया। कार्यक्रम के दौरान शांतिकुंज उप डाकघर की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय डाक विभाग ने विशेष पिक्टोरियल स्टैम्प जारी किया। स्टैम्प में शांतिकुंज संस्थापक पं.श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा की पावन समाधि स्थल का चित्र अंकित है। इस अवसर पर शांतिकुंज व्यवस्थापक योगेन्द्र गिरि, कुलसचिव बलदाउ देवांगन, प्रवर अधीक्षक डाकघर सचिन चौबे सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, अभिभावक और 02 हजार से अधिक नवप्रवेशी व पुराने छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

सीवान हिंसा : एके-47 से हवाई फायरिंग करने वाला एसआईटी जवान निलंबित

सीवान, (हि.स.)। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार बंद के दौरान सीवान में हुए हिंसक प्रदर्शन के बीच एके-47 से हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस जवान को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने विशेष जांच दल (एसआईटी) में तैनात जवान अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल, 25 जुलाई को गांधी मैदान और जेपी चौक के आसपास छात्र प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया, बैरिकेडिंग तोड़ दी और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिस जवान भीड़ के बीच एके-47 से हवाई फायरिंग करता दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने वायरल वीडियो की जांच कराई। प्रारंभिक जांच के बाद एसआईटी में तैनात जवान अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि मामले की विभागीय जांच जारी है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में सीवान के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पूरन कुमार झा समेत करीब 40 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एसपी के पैर में चोट लगी, जबकि कई अन्य पुलिसकर्मी और ड्यूटी पर तैनात पत्रकार भी पथराव में घायल हुए। पुलिस का दावा है कि उपद्रवियों ने पथराव के साथ पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल प्रयोग किया गया।

परिवार परम्परा एवं बिखरते रिश्ते पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि परिवार में बुजुर्गों की भूमिका को पुनः सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए, क्योंकि वे केवल अतीत के प्रतीक नहीं, बल्कि भविष्य के मार्गदर्शक हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी किसी न्यायिक टिप्पणी भर नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी का शंखनाद है। यदि हमने अभी भी अपने परिवारों को बचाने का प्रयास नहीं किया तो आने वाले वर्षों में केवल अदालतों में मुकदमे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि समाज की संवेदनाएं भी समाप्त होती जाएंगी। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है- 'वसुधैव कुटुम्बकम्।' लेकिन जो समाज अपने ही परिवार को नहीं बचा पाएगा, वह पूरी दुनिया को परिवार कैसे मान सकेगा? आज आवश्यकता नई इमारतें बनाने की नहीं, बल्कि बिखरते घरों को जोड़ने की है।

-: ललित गर्ग:-
****

परिवार केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग, धैर्य और संस्कारों का जीवंत विद्यालय है। जब इस विद्यालय की नींव कमजोर होने लगती है तो उसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है। देश के बहुचर्चित सोनम रघुवंशी 'हनीमून मर्डर' प्रकरण की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा व्यक्त की गई चिंता केवल एक अपराध पर की गई टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के बदलते चरित्र का गहन सामाजिक विश्लेषण थी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले ने जिस पीड़ा के साथ कहा कि संयुक्त परिवार लोगों को धैर्य, संयम, सहनशीलता और समायोजन सिखाते थे, वहीं आज एकल परिवारों में अवसाद, असहिष्णुता और संबंधों का विघटन बढ़ रहा है, वह हमारे समय का कटु सत्य है। माता-पिता और संतान, भाई-बहन, दादा-दादी और पोते-पोतियों के बीच भी भावनात्मक दूरी लगातार बढ़ रही है, यह परिवार परम्परा एवं रिश्तों में बढ़ती दूरी अब पति-पत्नी के बीच भी बड़ी दरारें डालने लगी है। रिश्तों का खोखलापन इतना बढ़ गया है कि अपनी ही पत्नी या पति की हत्या करने में भी तनिक संकोच नहीं रहा। ऐसे घटनाएं बार-बार देखने को मिल रही है। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु संवेदनाएं सिकुड़ती जा रही हैं। संवाद कम हो गए हैं और स्क्रीन का समय बढ़ गया है। परिणामस्वरूप रिश्ते धीरे-धीरे औपचारिकता में बदलते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में विवाह से पहले अथवा विवाह के कुछ ही दिनों बाद हुई इन नृशंस हत्याओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के पतन का संकेत है। जिन परिवारों में धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वहीं जीवन का सबसे बड़ा अभाव विश्वास और संतोष का था। संत कबीर का यह वचन आज पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है- 'जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान।' भौतिक संपन्नता कभी भी मानसिक शांति और रिश्तों की ऊष्मा नहीं खरीद सकती।

भारतीय संस्कृति ने परिवार को केवल सामाजिक संस्था नहीं माना, बल्कि धर्म, संस्कृति और जीवन-मूल्यों का प्रथम विद्यालय माना है। संयुक्त परिवार में दादा-दादी केवल बुजुर्ग नहीं होते थे, वे अनुभवों के विश्वविद्यालय होते थे। नाना-नानी केवल रिश्तेदार नहीं, बल्कि संस्कारों के संरक्षक होते थे। बच्चों को कहानियों के माध्यम से धैर्य, करुणा, क्षमा, संयम और त्याग का पाठ पढ़ाया जाता था। घर का हर सदस्य दूसरे के दुःख का सहभागी होता था। इसलिए किसी एक व्यक्ति का तनाव पूरे परिवार की शक्ति से हल्का हो जाता था। आज यह सुरक्षा-कवच तेजी से टूट रहा है। महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में पति-पत्नी दोनों कार्यस्थल पर व्यस्त हैं। बच्चों का बचपन मोबाइल, टैबलेट और घरेलू सहायिकाओं के भरोसे बीत रहा है। जब बच्चा रोता है तो उसे गोद नहीं, मोबाइल थमा दिया जाता है। यह सुविधा का समाधान नहीं, संवेदनाओं का विस्थापन है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि 'भावनाओं का विकल्प गैजेट्स नहीं हो सकते', हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक चेतावनी है।

डिजिटल क्रांति ने जीवन को सरल अवश्य बनाया है, लेकिन यदि तकनीक मनुष्य पर हावी हो जाए तो वह संबंधों की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। आज परिवार एक ही कमरे में बैठकर भी अलग-अलग दुनिया में खोया रहता है। भोजन की मेज पर संवाद समाप्त हो गया है। आंखों में आंखें डालकर बातें करने की परंपरा लुप्त होती जा रही है। इससे भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ रहा है और अकेलापन बढ़ रहा है। इस पूरे संकट की जड़ केवल आधुनिकता नहीं है। समस्या आधुनिकता के असंतुलित और अंधानुकरण में है। पश्चिम से हमने तकनीक तो अपनाई, लेकिन उसकी सामाजिक चुनौतियों से सीख नहीं ली। अब पति और पत्नी के बीच तीसरा आना आम बात हो गयी है, और यही तीसरा समस्या की जड़ है। इस तरह के अवैध रिश्तों ने त्रासद घटनाओं को जन्म दिया है। भारतीय परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी-'मैं' से पहले 'हम' का भाव। आज 'हम' की जगह 'मैं' ने ले ली है। अधिकारों की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन कर्तव्यों का स्मरण बहुत कम होता है। रिश्तों में बढ़ता अहंकार भी विघटन का बड़ा कारण है। पति-पत्नी दोनों अपने-अपने तर्कों को अंतिम सत्य मानने लगे हैं। कोई झुकना नहीं चाहता। जबकि भारतीय परंपरा ने सिखाया था कि झुकना हार नहीं, बल्कि संबंधों को बचाने की सबसे बड़ी जीत है। क्षमा और संवाद हर टूटते रिश्ते की पहली दवा हैं, किंतु आज संवाद की जगह आरोप और क्षमा की जगह प्रतिशोध ने ले ली है। यह भी विचारणीय है कि आज विवाह को जीवनभर का संस्कार नहीं, बल्कि सुविधानुसार निभाया जाने वाला अनुबंध समझा जाने लगा है। यही कारण है कि छोटी-छोटी असहमतियां भी अदालतों तक पहुंच रही हैं। न्यायालय न्याय दे सकता है, लेकिन प्रेम नहीं लौटा सकता। कानून अधिकारों का संरक्षण कर सकता है, लेकिन आत्मीयता का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए पारिवारिक समस्याओं का स्थायी समाधान न्यायालयों में नहीं, परिवारों के भीतर ही खोजा जाना चाहिए। भारत आज विश्वगुरु बनने का स्वप्न देख रहा है। आर्थिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियां, डिजिटल नवाचार और वैश्विक नेतृत्व निश्चित रूप से गर्व के विषय हैं। लेकिन यदि हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति 'संयुक्त परिवार' कमजोर हो जाएगी, तो यह प्रगति अधूरी रह जाएगी। विश्व भारत से केवल आर्थिक शक्ति की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उन जीवन-मूल्यों की भी अपेक्षा करता है जिन्होंने हजारों वर्षों तक इस सभ्यता को जीवित रखा है। विश्वगुरु वही बन सकता है जो अपने परिवारों को भी मजबूत रख सके। जिस समाज में माता-पिता उपेक्षित हों, बुजुर्ग अकेले हों, बच्चे भावनात्मक रूप से असुरक्षित हों और पति-पत्नी विश्वास के संकट से जूझ रहे हों, वह केवल आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, सांस्कृतिक महाशक्ति नहीं।

समय आ गया है कि परिवारों में पुनः संवाद की संस्कृति विकसित की जाए। सप्ताह में कुछ समय ऐसा हो जब पूरा परिवार बिना मोबाइल के साथ बैठे। बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, अच्छे संस्कार भी मिलें। विद्यालयों में जीवन-मूल्य और भावनात्मक शिक्षा को महत्व दिया जाए। विवाह-पूर्व परामर्श, पारिवारिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाए।

संम्पादकीय

पत्रकारिता और राजनीति : आज़ादी की लड़ाई से सत्ता के गलियारों तक

प्रमोद भार्गव
****

भारतीय लोकतंत्र की सबसे जटिल और सबसे निर्णायक साझेदारियों में यदि किसी एक रिश्ते का नाम लिया जाए, तो वह है पत्रकारिता और राजनीति। दोनों का जन्म अलग-अलग उद्देश्यों से हुआ, लेकिन दोनों का अंतिम दायित्व जनता के प्रति है। एक सत्ता का संचालन करती है, दूसरी सत्ता की निगरानी। जब दोनों अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हैं, तब लोकतंत्र मजबूत होता है; लेकिन जब दोनों की सीमाएँ धुंधली होने लगती हैं, तब लोकतंत्र का संतुलन भी डगमगाने लगता है। आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता सत्ता के गलियारों की नहीं, जनसंघर्ष की आवाज़ थी। अखबार व्यापार नहीं, विचार थे; संपादक मालिक नहीं, आंदोलनकारी थे। राजा राममोहन राय से लेकर बाल गंगाधर तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी और बाबूराव विष्णु पराड़कर तक, पत्रकारिता ने केवल समाचार नहीं दिए—उसने राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया। अंग्रेज़ी शासन के लिए अखबार सबसे बड़ा खतरा थे, क्योंकि वे जनता को जागृत करते थे। उस दौर की राजनीति भी सत्ता प्राप्ति का अभियान नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति का संकल्प थी। पत्रकार और राजनेता वैचारिक बहस करते थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य राष्ट्र था। इसलिए पत्रकारिता राजनीति की सहयोगी नहीं, उसकी नैतिक प्रेरक शक्ति थी। स्वतंत्रता के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं। विदेशी शासन समाप्त हुआ और लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हुईं। पत्रकारिता का दायित्व भी बदल गया। अब उसका काम किसी सत्ता को हटाना नहीं, बल्कि हर सत्ता को संविधान और जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखना था। नेहरू युग में आलोचना और असहमति के लिए अपेक्षाकृत खुला वातावरण था। सरकारें आलोचना से असहज अवश्य होती थीं, लेकिन लोकतांत्रिक संवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यह वह समय था जब संपादक संस्थानों की आत्मा हुआ करते थे और संपादकीय नीति का निर्धारण समाचार कक्ष में होता था, न कि कॉर्पोरेट बोर्डरूम में। फिर आया 1975 का आपातकाल—भारतीय पत्रकारिता का सबसे अंधकारमय अध्याय। सेंसरशिप लागू हुई, समाचारों पर सरकारी पहरा बैठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला जड़ दिया गया। उसी दौर की वह टिप्पणी आज भी पत्रकारिता के इतिहास में दर्ज है—÷जब प्रेस से झुकने को कहा गया, तो कई लोग रेंगने लगे।÷ लेकिन इसी दौर ने यह भी सिद्ध किया कि कलम की असली ताकत सत्ता की प्रशंसा में नहीं, उसके सामने सच लिखने में है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने मीडिया को नई तकनीक, नई पूंजी और नई संभावनाएँ दीं। निजी समाचार चैनलों की बाढ़ आई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और पत्रकारिता एक बड़े उद्योग का रूप लेने लगी। यह परिवर्तन स्वाभाविक था, लेकिन इसके साथ एक नया संकट भी पैदा हुआ—समाचार और बाज़ार के बीच बढ़ती निर्भरता। धीरे-धीरे टीआरपी, विज्ञापन, ब्रांड प्रबंधन और कॉर्पोरेट हित संपादकीय निर्णयों को प्रभावित करने लगे। समाचार जनहित से अधिक दर्शक-हित और विज्ञापन-हित की कसौटी पर परखे जाने लगे। राजनीति ने भी मीडिया की ताकत को समझा और जनसभाओं के साथ-साथ मीडिया प्रबंधन, छवि निर्माण तथा नैरेटिव नियंत्रण को चुनावी रणनीति का अभिन्न हिस्सा बना लिया। डिजिटल युग ने इस रिश्ते को और अधिक जटिल बना दिया। सोशल मीडिया ने सूचना का लोकतंत्रीकरण तो किया, लेकिन सत्य का नहीं। अब सूचना सबसे तेज़ है, सत्य अक्सर सबसे धीमा। हर हाथ में कैमरा है, हर मोबाइल एक प्रसारण केंद्र है और हर व्यक्ति स्वयं को पत्रकार घोषित कर सकता है। लेकिन पत्रकारिता केवल सूचना का प्रसार नहीं; तथ्यों की पुष्टि, संदर्भों की व्याख्या और जनहित में सत्ता से प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी भी है। आज राजनीति डिजिटल अभियानों, ट्रोल तंत्र, डेटा विश्लेषण और नैरेटिव निर्माण के माध्यम से जनमत को प्रभावित करती है। दूसरी ओर मीडिया का एक वर्ग सत्ता के अधिक निकट दिखाई देता है, जबकि दूसरा वर्ग हर मुद्दे को टकराव के चश्मे से देखता है। इस वैचारिक ध्रुवीकरण में सबसे बड़ी क्षति निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की हुई है। सवाल यह नहीं कि पत्रकारिता समाप्त हो गई है। सवाल यह है कि उसकी प्राथमिकताएँ बदल गई हैं। फिर भी तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। आज भी अनेक पत्रकार सीमित संसाधनों और गंभीर जोखिमों के बीच भ्रष्टाचार, अपराध, पर्यावरण, न्याय और हाशिए के समाज की आवाज़ को सामने ला रहे हैं। यही लोग इस पेशे की विश्वसनीयता को बचाए हुए हैं। लोकतंत्र में पत्रकारिता का दायित्व सरकार का प्रचार करना नहीं, बल्कि सरकार से प्रश्न पूछना है। उतना ही आवश्यक है कि वह विपक्ष से भी उतनी ही कठोरता से जवाब मांगे। सत्ता समर्थक या सत्ता विरोधी होना पत्रकारिता नहीं है; जनता समर्थक होना ही पत्रकारिता का धर्म है। आज भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रेस की स्वतंत्रता जितनी ही उसकी विश्वसनीयता भी है। स्वतंत्रता बिना विश्वसनीयता के अराजकता बन जाती है और विश्वसनीयता बिना स्वतंत्रता के प्रचार। लोकतंत्र अंततः विश्वास पर खड़ा होता है—जनता का राजनीति पर विश्वास और जनता का पत्रकारिता पर विश्वास। यदि राजनीति जवाबदेही छोड़ दे और पत्रकारिता प्रश्न पूछना बंद कर दे, तो लोकतंत्र केवल चुनावों का उत्सव रह जाएगा, जनसरोकारों का नहीं। अंततः पत्रकारिता का धर्म सत्ता के साथ चलना नहीं, सत्ता के सामने सच लिखना है। सिंहासन समय के साथ बदलते रहते हैं, सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन सच लिखी हुई पंक्तियाँ इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। लोकतंत्र की रक्षा संसद जितनी करती है, उतनी ही एक निर्भीक कलम भी करती है—और यह जिम्मेदारी आज पहले से कहीं अधिक बड़ी है। हालांकि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेकर उन्होंने जंतर-मंतर से आंदोलन तो खत्म करवा दिया है, बस इसी से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद अब मोदी चौन से बैठ पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पिछले बारह सालों की उनकी राजनीतिक चतुराई और सत्ता पर बने रहने की कला को इस बार सबसे बड़ी चुनौती मिली है, वो भी सीधे नयी पीढ़ी की तरफ से। जो न गोदी मीडिया के एजेंडे पर कान धरती है, न सरकारी दबाव की उसे परवाह है। दरअसल भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे को मीडिया के बड़े हिस्से ने लगातार खाद-पानी दिया। इससे तथाकथित पत्रकारों की और उनके मालिकान की दुकानदारी खूब फली-फूली और सत्ता के जरिए लोकतंत्र और संविधान को कुचलने के काम में भाजपा को आसानी हुई। पिछले बारह सालों में अनगिनत बार इस बात पर चिंता जताई जाती रही कि जो खुद को मुख्यधारा का मीडिया कहता है, वहां मुख्य मुद्दे यानी जनता के हित से जुड़े मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती और हर बात में हिंदू-मुसलमान एंगल खड़ा कर दिया जाता है। खुद विपक्षी दल सरेआम कई पत्रकारों को कह चुके कि आप मोदी के मित्र उद्योगपतियों और भाजपा के लिए काम करते हैं। निष्पक्ष खबरें नहीं दिखाते और हमारी खबरों को गायब करते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के तो कई बयान सोशल मीडिया पर हैं, जिनमें वे मीडिया पर तंज कसते हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों ने ऐसे मीडिया का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं किया, जिसने पेशेवर बेईमानी की।

आज का राशिफल

मेष
निकट संबंधों में शंकाओं को हावी न होने दें। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। नौकरी का वातावरण सुखद होगा। सगे-संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

वृषभ
आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी।

मिथुन
नकारात्मक चिंताओं का त्याग करें। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। वर्तमान में आपको सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में प्रयास करना चाहिए।

कन्या
किसी नये कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए मन केंद्रित होगा। नवीन योजनाओं द्वारा प्रगति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

धनु
मन सुंदर कल्पनाओं से प्रभावित रहेगा। नये संबंधों के प्रति निकटता बढ़ेगी। उपस्थित साधनों में सन्तुष्ट व तृप्त होने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।

मकर
विभागीय परिवर्तनों से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अन्दर धैर्य व वाणी में मधुरता लावें। कुछ नई अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी। प्रियजनों का सनिध्य प्राप्त होगा।

कुंभ
संबंधों में कटु वचनों का प्रयोग न करें। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अच्छे कायरे द्वारा प्रशंसा के पात्र बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा।

कर्क
बीती बातों को भूलने की कोशि करें। रोजगार में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। भौतिक इच्छाएं बलवती होंगी। अभिभावकों के भावनात्मक सहयोग से उत्साह में वृद्धि होगी।

तुला
महत्वाकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरें में अत्याधिक व्यय का योग है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार में सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी।

वृश्चिक
परिश्रम का समुचित लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा।

मीन
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। अच्छे कायरे के लिए प्रशंसनीय होंगे। शासन-सत्ता से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा।

मीन
आवेश में किये गये कार्य से कष्ट संभव। भावनात्मक समस्याओं पर सगे-संबंधियों के बीच खुलकर बात करें। कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे।

प्रधान का नुकसान क्या राहुल का फायदा है?

प्रभु चावला
****

राजनीतिक आंदोलनों ने अक्सर सरकारों की दिशा बदल दी है। कुछ आंदोलनों ने सत्ता को उखाड़ फेंका है, कुछ ने नीतियों में उलटफेर किया है और कुछ ने शक्तिशाली सरकारों को जनता के गुस्से को शांत करने के लिए मंत्रियों की बलि देने पर मजबूर किया है। यही कुछ इस सप्ताहांत नई दिल्ली में देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल से कहीं अधिक है। यह 12 वर्षों में पहली बार है कि निरंतर जन आंदोलन, जिसे विपक्ष के लगातार दबाव से बल मिला, नरेंद्र मोदी सरकार में किसी कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे का कारण बना। जैसी कि उम्मीद थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे को 'भारत के युवाओं की जीत' बताया। भाजपा ने इस व्याख्या को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के व्यापक हित में काम किया है। इन परस्पर विरोधी राजनीतिक बयानों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है-क्या यह इस्तीफ़ा एक अलग-थलग रियायत है, या इसने मोदी सरकार द्वारा एक दशक से सावधानीपूर्वक बनाए गए राजनीतिक अजेयता के आभास को परास्त कर दिया है? या इसने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले हतोत्साहित विपक्ष को फिर से सक्रिय कर दिया है? दिल्ली की भीषण गर्मी में, राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर पालथी मारकर धरने पर बैठे थे, जबकि जंतर-मंतर से, जो उनसे बस एक किलोमीटर दूर था, 'प्रधान हटाओ' के नारे गूंज रहे थे। हफ्तों से यही दृश्य दोहराया जा रहा था-कोचिंग सैंटर के छात्रों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, संसद के पास प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा था और विपक्षी नेताओं का एक समूह बारी-बारी से माइक पर आकर नीट-यूजी पेपर लीक कांड को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। शनिवार को यह मांग पूरी हुई। एक ऐसी सरकार के लिए जिसने 12 साल तक कभी पीछे न हटने की कला में महारत हासिल की थी, यह एक दुर्लभ और शर्मनाक कदम था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, यू.पी.ए. के 10 साल के कार्यकाल में लगभग आधा दर्जन मंत्रियों ने इसी तरह के दबाव में इस्तीफ़ा दिया था। प्रधान का इस्तीफ़ा एक अटूट सिलसिले को तोड़ता है और जिसे एक असामान्य तालमेल के माध्यम से हासिल किया गया-राहुल गांधी और कांग्रेस ने धरने और संसदीय व्यवधान का नेतृत्व किया, समाजवादी पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक के क्षेत्रीय सहयोगियों ने उनका साथ दिया, शिक्षा कार्यकर्त्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों की भूख हड़ताल की और काक्रोच जनता पार्टी नामक एक युवा-संचालित विरोध आंदोलन ने उन छात्रों को लामबंद किया जिन्होंने पहले कभी पार्टी की राजनीति में भाग नहीं लिया था। एक इस्तीफे से 12 वर्षों का चुनावी वर्चस्व खत्म नहीं हो जाता और सरकार का अपना तर्क इसके विपरीत एक अलग कहानी पेश करता है-प्रधान ने अपने शब्दों में 'छात्रों के व्यापक हित में' इस्तीफ़ा दिया, न कि किसी अपराध को स्वीकार करते हुए। मोदी ने परीक्षा प्रणाली में किसी भी गहरी व्यवस्थागत विफलता को स्वीकार नहीं किया है। सी.बी.आई. की मौजूदा जांच, रद्द हुई परीक्षा और दोबारा परीक्षा, खबरों के शांत होने के बाद शायद सरकार की हार मानने की बजाय निर्णायक कदम के रूप में सामने आ सकती है। आलोचकों का कहना है कि भाजपा ने इससे कहीं बड़े विवादों का सामना बिना झुके किया है और एक इस्तीफ़ा, चाहे वह कितना भी प्रतीकात्मक क्यों न हो, राष्ट्रीय विपक्ष को पुनर्जीवित करने का कमजोर आधार है। मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और भाजपा की संगठनात्मक क्षमता, ज्यादातर मामलों में, काफी हद तक बरकरार है। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषक इस क्षण को मात्र प्रतीकात्मक नहीं मान रहे। राहुल गांधी के उस करियर में यह पहली ठोस जीत है, जो नारों से अधिक परिणामों से परिभाषित हुआ है। कांग्रेस रणनीतिकारों के लिए सबक यह है कि शिकायत की राजनीति, जब मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले किसी मुद्दे, जैसे धांधली वाली परीक्षा, छीना गया भविष्य, के साथ जोड़ दी जाए, तो यह अन्यथा प्रभावशाली भाजपा के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकती है। क्या यह आगामी राज्य चुनावों में कारगर साबित होगी? अब असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में होगी, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल पहले ही इन विरोध प्रदर्शनों में राहुल और प्रियंका के साथ खड़े हो चुके हैं और उन्होंने पहले के चुनाव प्रचारों के 'यू.पी. के लड़के, यू.पी. की लड़कियां' नारे को फिर से जीवित कर दिया है, जिनसे चुनाव में निराशाजनक परिणाम मिले थे। कांग्रेस के रणनीतिकार अब प्रधान के इस्तीफे को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे-यह साबित करना कि सरकार को झुकाया जा सकता है और उन्हीं छात्र और मध्यमवर्गीय मतदाताओं को एकजुट करना, जो नीट घोटाले से खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। राजनीतिक सत्ता का क्षरण तब शुरू नहीं होता जब कोई मंत्री इस्तीफ़ा देता है, बल्कि तब शुरू होता है, जब नागरिकों को पता चलता है कि सबसे शक्तिशाली सरकार भी जन दबाव के आगे झुकने को विवश हो सकती है।

अमेरिका-ईरान के बीच हमले रुके, होर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराया टैंकर, धमाका

तेहरान/वाशिंगटन, । मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में हमले तो रुक गए हैं पर होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। होर्मुज में एक तेल टैंकर के बारूदी सुरंग से टकराने के बाद जोरदार धमाका हुआ है। अमेरिका ने फिलहाल ईरान के खिलाफ अपने हमले रोक दिए हैं। तेहरान को भी लगभग दो सप्ताह की बमबारी के बाद इस इलाके में अपने जवाबी हमले रोकने पड़े हैं।

अल जजीरा और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना के पास गोला-बारूद कम होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का कहना है कि अमेरिका पूर्व की बातचीत के अपघात कर चुका है। बावजूद इसके तेहरान और वाशिंगटन मध्यस्थों के माध्यम से संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे हैं।

ईरान के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहा एक तेल टैंकर बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद धमाके का शिकार हो गया। यह टैंकर ईरानी अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी कर आगे बढ़ रहा था।

होर्मुज में यह घटना दो दिनों की शांति के बाद हुई है।संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने रविवार को कहा कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार 13वीं रात अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप प्रशासन ने कूटनीतिक प्रयासों को देखते हुए अनिश्चित समय तक हमले रोकने का फैसला किया है। उधर, पाकिस्तान, कतर और मध्य पूर्व के अन्य देश अमेरिका और ईरान को फिर शांति की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।ईरानी सेना ने भी कहा कि उसने मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों पर जवाबी हमले रोक दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एआई निर्मित कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इनमें अमेरिका की सैन्य ताकत को दिखाया गया है और उसे दुनिया का रक्षक बताया गया है। यह तस्वीरें अमेरिका की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी रेखांकित करती हैं।

हूती विद्रोहियों का दावा- सऊदी अरब के तेल आपूर्ति नेटवर्क को बनाया निशाना

सना/रियाद,। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों को लाल सागर स्थित यानबू निर्यात केंद्र से जोड़ने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति और परिवहन नेटवर्क से जुड़े कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है।

हूती संगठन के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि यह कार्रवाई सऊदी अरब द्वारा यमन के हवाई क्षेत्र में कथित ड्रोन गतिविधियों के जवाब में की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी ड्रोन लगातार यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं।

उधर, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने इस दावे पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के कारण सऊदी अरब अपने पूर्वी तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल को पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन के जरिए लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचा रहा है, ताकि तेल निर्यात सुचारु रूप से जारी रह सके।

कपिल सिब्बल से मिले सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके, बोले- आंदोलन खत्म हुआ है लड़ाई नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। 36 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद रविवार को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से मुलाकात की. उन्होंने संकेत दिए कि प्रदर्शन भले समाप्त हो गया हो, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई अभी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि सीजेपी जल्द ही अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेगी. प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज मामलों को हटाने को लेकर भी कानूनी स्तर पर बातचीत जारी है. जल्द बताएंगे आगे क्या होगाः कपिल सिब्बल के आवास के बाहर अभिजीत दीपके से प्रदर्शन के बाद की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संगठन अभी आगे की योजना तैयार कर रहा है. प्रदर्शन अभी एक दिन पहले ही समाप्त हुआ है, इसलिए पूरी रणनीति तय करने के लिए थोड़ा समय चाहिए. दीपके ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही संगठन अपनी अगली कार्ययोजना सार्वजनिक करेगा. पंजाब पेपर लीक मामले पर भी बनाएंगे रणनीतिः पंजाब में सामने आए कथित पेपर लीक मामले पर सवाल किया गया तो दीपके ने कहा कि संगठन इस मुद्दे पर भी काम कर रहा है. इस विषय पर भी जल्द अपनी बात रखी जाएगी और फिलहाल संगठन इसकी योजना बनाने में जुटा है. सीजेपी भविष्य में अन्य राज्यों में परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक से जुड़े मामलों को भी अपने अभियान का हिस्सा बना सकती है. छात्रों पर दर्ज मामलों को हटाना पहली प्राथमिकताः उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरी प्राथमिकता आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर है.

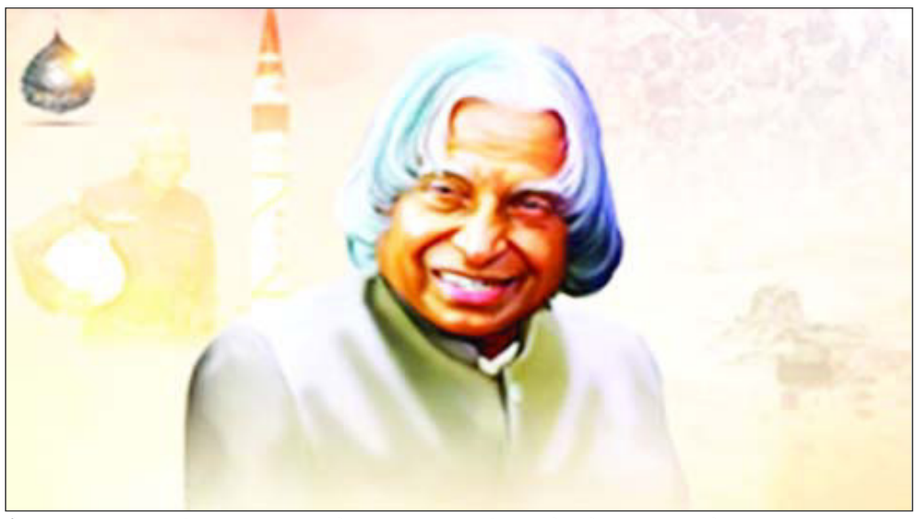

पुण्यतिथि पर डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम को अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और 'मिसाइलमैन' डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीयों मंत्रियों ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक्स पर लिखा, 'देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 'मिसाइल मैन' डॉ. कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्नदृष्टा थे। स्वदेशी मिसाइल एवं अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान भारतीय विज्ञान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने ज्ञान, अनुशासन, सादगी और राष्ट्रसेवा को अपने जीवन का आधार बनाया तथा देश के करोड़ों युवाओं में आत्मविश्वास, नवाचार और राष्ट्रनिर्माण का भाव जागृत किया। 'सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने न दें', डॉ. कलाम के ऐसे विचार आज भी हर युवा को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते हैं।' केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, 'भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों के दूरदर्शी और सूत्रधार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। विज्ञान के क्षेत्र में डॉ. कलाम जी की असाधारण उपलब्धियों ने भारत

को एक मजबूत रणनीतिक शक्ति बनाने का रास्ता दिखाया, और उनकी बुद्धिमत्ता ने लोगों को महानता हासिल करने के लिए प्रेरित करके लाखों जिंदगियों को रोशन किया। 'जनता के राष्ट्रपति' डॉ. कलाम हमेशा देशभक्तों के लिए एक आदर्श बने रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर, मैं 'पीपल्स प्रेसिडेंट' (जनता के राष्ट्रपति), 'मिसाइल मैन ऑफ़ इंडिया' और एक असाधारण वैज्ञानिक व दूरदर्शी व्यक्ति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने भारत की स्वदेशी मिसाइल और रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति अटूट समर्पण से भरा उनका जीवन पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, निडर होकर नई खोजें करने और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'भारत को सामरिक एवं परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के क्षेत्र में सशक्त बनाने में बहुमूल्य योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं 'भारत रत्न' डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन। ' जेपी नड्डा ने आगे कहा, 'रक्षा एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल कार्यक्रम, एसएलवी-3 के विकास, रोहिणी उपग्रह के सफल प्रक्षेपण तथा पोखरण-द्वद्व परमाणु परीक्षणों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने भारत की वैज्ञानिक और सामरिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया। उनके अमूल्य विचार, दूरदर्शी नेतृत्व और आदर्श जीवन सदैव युवाओं को राष्ट्र निर्माण एवं समाज सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ' केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट किया, 'महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, देश के पूर्व राष्ट्रपति, 'भारत रत्न' डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र उत्थान के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी को शिक्षित, सशक्त, समर्थ और गौरवशाली भारत के निर्माण में हरसंभव योगदान के लिए सर्वदा प्रेरित करता रहेगा।

यूक्रेन युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया सैन्य सेवा की अवधि बढ़ाने की योजना बना रहा

वियना, । यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए ऑस्ट्रिया की गठबंधन सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने की योजना की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में देश की सुरक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक हो गया है।ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने साल्जबर्ग के निकट एक सैन्य बैरक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों और विशेष रूप से हाल के महीनों में यूरोप की सुरक्षा स्थिति में बुनियादी बदलाव आया है। उन्होंने

कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप में स्थायी शांति की धारणा को गहरा झटका पहुंचाया है।स्टॉकर ने कहा कि पारंपरिक सैन्य चुनौतियों के साथ-साथ अब हाइब्रिड हमलों और साइबर युद्ध जैसे नए खतरे भी सामने आए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रिया को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक सक्षम बनने की जरूरत है।तटस्थ नीति अपनाने वाले ऑस्ट्रिया की सेना लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं, सीमा सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं में सहयोग जैसे कार्यों पर अधिक केंद्रित रही है। हालांकि, सरकार का मानना है कि वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण जरूरी है।

सरकार की योजना के अनुसार, सैन्य सेवा के साथ-साथ वैकल्पिक नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) को भी स्वैच्छिक आधार पर दो महीने तक बढ़ाने का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा, सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए रिजर्विस्ट प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत उन्हें अगले दस वर्षों के भीतर समय-समय पर प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेना होगा।

असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, 5.24 लाख लोग प्रभावित

2 और मौतों से मृतकों की संया बढ़कर 68 हुई

गुवाहाटी, एजेंसी। असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार को और सुधार हुआ, हालांकि पांच जिलों में 5.24 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी प्रभावित हैं, जबकि दो और मौतों के साथ इस साल की बाढ़ में मरने वालों की संख्या 68 हो गई. एक सरकारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर जिलों में 5,24,700 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. रविवार देर रात जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान चराईदेव जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से दो और लोगों की जान चली गई.

चराईदेव सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, जहाँ लगभग 1.9 लाख लोग प्रभावित हैं. इसके बाद शिवसागर (1.5 लाख से ज़्यादा) और जोरहाट (लगभग 1.4 लाख) हैं. शनिवार से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, जब छह जिलों में लगभग 6.55 लाख लोग प्रभावित हुए थे. एएसडीएमए ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन चार जिलों में 354 रिलीफ कैंप और मदद बांटने वाले सेंटर चला रहा है और 37,724 बेघर लोगों का ध्यान रख रहा है. आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ , फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और पुलिस जैसी कई एजेंसियों ने ऊपरी असम के अलग-अलग हिस्सों से कई लोगों को बचाया है, ऐसा कहा गया है. अभी पूरे असम में 763 गांव पानी में हैं और 48,742.09 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है, ऐसा कहा गया है. बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य के अलग-अलग जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है. एएसडीएमए ने कहा कि नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बड़े पैमाने पर बाढ़ की वजह से पूरे असम में 88,240 पालतू जानवर और मुर्गी पालन पर असर पड़ा है, ऐसा कहा गया है.

खेती-किसानी और बेजुबानों पर भारी मारः बाढ़ ने न केवल इंसानी जिंदगी बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ दी है। राज्य भर के 763 गांव पूरी तरह जलमग्न हैं और लगभग 48,742.09 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म...अब क्या राजनीति में एंट्री करेंगे दीपके

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद नई दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी प्रदर्शन क्षेत्र की साफ-सफाई करने में जुटे हैं। वहीं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके समर्थक भी वापस लौट चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि सीजेपी अब आगे क्या करेगी? क्या दीपके कोई अपनी कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे जंतर-मंतर पर चले इस आंदोलन को पूरी तरह गैर-राजनीतिक बताया गया, हालांकि इसके मंच पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार गुट) सहित कई विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। फिल्म और खेल जगत की कुछ हस्तियां भी आंदोलन के समर्थन में दिखाई दीं। इसके बावजूद छ्छ्क ने खुद को किसी राजनीतिक दल के रूप में पेश नहीं किया।

आंदोलन ने छात्रों में नई ऊर्जा पैदा की: जेएनयू के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के प्रोफेसर डॉ. सुधीर कुमार ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि, सीजेपी ने अब तक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। उनके मुताबिक, इस आंदोलन ने छात्रों में नई ऊर्जा पैदा की है। पिछले कई वर्षों में शिक्षा से जुड़े कई आंदोलन हुए, लेकिन सीजेपी ने उन्हें फिर से सक्रिय करने का काम किया। साथ ही विपक्षी दलों ने भी छात्रों की मांगों को गंभीरता से उठाना शुरू किया। वहीं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उनके मुताबिक, इस आंदोलन ने यह संदेश दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि उनका मानना है कि सीजेपी को राजनीतिक पार्टी नहीं बनना चाहिए। उनके अनुसार, यदि यह आंदोलन राजनीतिक दल में बदलता है तो इसकी नैतिक ताकत और विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है।

कई राजनीतिक दल छात्र आंदोलनों से ही निकले: एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर की राय अलग है। उनका कहना है कि भारत में कई राजनीतिक दल छात्र आंदोलनों से ही निकले हैं। उन्होंने 1974 के जेपी आंदोलन और बाद में बनी जनता पार्टी का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, सीजेपी भले ही खुद को राजनीतिक दल नहीं कह रही हो, लेकिन उसके मुद्दे और बयान राजनीतिक हैं। इसलिए भविष्य में इसके राजनीतिक मंच बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सोशल मीडिया से सड़क तक का सफर

सीजेपी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्य के रूप में हुई थी। मई में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद 'कॉकरोच' शब्द सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद सीजेपी नाम से वेबसाइट बनी, सोशल मीडिया पर लाखों लोग जुड़े और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अभियान शुरू हुआ। 6 जून को पहला प्रदर्शन हुआ और 20 जून से जंतर-मंतर पर लगातार आंदोलन शुरू हो गया। आखिरकार एक महीने बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। विश्लेषकों का कहना है कि इस आंदोलन ने यह दिखाया कि आज के युवा केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे नीतियों और फैसलों में अपनी भागीदारी भी चाहते हैं। वहीं आशुतोष का मानना है कि सीजेपी ने जेन-जी के अंदर लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत किया है। इस आंदोलन ने यह धारणा भी बदली कि आज के युवा केवल सोशल मीडिया तक सीमित हैं।

सीजेपी का आगे क्या होगा

फिलहाल सीजेपी का आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ विशेषज्ञ इसे एक सफल छात्र आंदोलन मानते हैं, जबकि कुछ इसके भीतर भविष्य की राजनीतिक ताकत देखते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सीजेपी नए मुद्दों पर फिर सक्रिय होती है या इसके उठाए गए मुद्दों को विपक्षी दल आगे बढ़ाते हैं। इतना तय है कि इस आंदोलन ने देश में

कॉकरोचों के बाद शुरू हुआ ई20 आंदोलन, क्यों मांगा जा रहा गडकरी का इस्तीफा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में ई20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। वाहन मालिकों, कुछ एक्टिविस्टों और विपक्ष के एक वर्ग का कहना है कि सरकार द्वारा श्व20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को 100% पेट्रोल (बिना एथेनॉल मिश्रण) खरीदने का विकल्प भी मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरित एक समूह 'ई20 जनता पार्टी' नाम से अभियान चला रहा है। इस अभियान के साथ कुछ विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। हालांकि, पहले ही गडकरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं और एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का बचाव किया है।

क्यों उठ रही है इस्तीफे की मांग: विरोध करने वालों का कहना है कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कुछ वाहनों की माइलेज में कथित तौर पर 8% से 15% तक कमी देखी गई है। उनका आरोप है कि पुराने वाहनों में इससे इंजन, फ्यूल पंप और फ्यूल टैंक पर अतिरिक्त घिसाव या जंग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे वाहन मालिकों का मेंटेनेंस खर्च बढ़ता है। इसके अलावा, कुछ विरोधी समूहों ने हितों के टकराव का मुद्दा भी उठाया है। उनका दावा है कि नितिन गडकरी के परिवार से जुड़े कुछ कारोबारी हितों को एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति से लाभ हो सकता है। इन आरोपों के आधार पर उन्होंने अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है।

यूपी में लगेंगे 238 नए पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और 714 चार्जर

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हरित परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव स्कीम और उत्तर प्रदेश की ईवी मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी-2022 के तहत प्रदेश में 238 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम तेज किया जा रहा है। यह पहल राज्य में चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। पहले चरण में 238 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे, जिन पर 714 चार्जर लगाए जाएंगे। इन स्टेशनों के संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध प्रस्तावित है। सरकारी भूमि पर स्थापित होने वाले इन चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग केवल ईवी चार्जिंग गतिविधियों के लिए होगा तथा संबंधित विभागों से 1रूपये प्रति किलोवाट की दर से भूमि उपयोग शुल्क लिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशनों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। सरकारी कार्यालयों में स्थापित होने वाले स्टेशनों को अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवीएसई पर 100 प्रतिशत तक सहायता का प्रावधान है, जबकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी अलग-अलग स्तर पर सब्सिडी का प्रस्ताव है। योजना का उद्देश्य शहरों के साथ-साथ प्रमुख हाईवे पर भी चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना है। उत्तर प्रदेश ईवी मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी-2022 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके साथ ही व्यापक चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क विकसित करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना तथा ईवी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी प्रमुख उद्देश्य हैं। राज्य सरकार की नीति में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए पूंजीगत प्रोत्साहन और सरकारी भूमि उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान पहले से मौजूद हैं। गौतमबुद्ध नगर में 39, लखनऊ में 36, मेरठ में 35, गोरखपुर में 32, वाराणसी में 28, आगरा में 21, मथुरा में 14, प्रयागराज में 13, कानपुर नगर में 12, गाजियाबाद में 6, कानपुर देहात में 2 समेत कुल मिलाकर 238 स्थानों की पहचान की गई है। कई विभागों की जमीन होगी उपयोग में प्रस्ताव के अनुसार चार्जिंग स्टेशन नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, विद्युत वितरण कंपनियों, यूपीएसआरटीसी, जिला प्रशासन तथा अन्य सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। इसमें नोएडा, लखनऊ नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, मेरठ नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम सहित अनेक सरकारी संस्थाओं की भूमि शामिल है। शहर के अंदर और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं। शहरों में लगभग 40,60 वर्गमीटर और हाईवे पर बड़े चार्जिंग हब के लिए 250,300 वर्गमीटर तक भूमि की आवश्यकता बताई गई है। हाईवे स्टेशनों पर बसों और ट्रकों के लिए उच्च क्षमता वाले डीसी फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। हाल के दिनों में मुख्य सचिव स्तर पर विभिन्न विभागों से उपलब्ध सरकारी भूमि का ब्योरा मांगा गया है ताकि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसका उद्देश्य राज्य में ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए मजबूत सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।

संक्षिप्त समाचार

नेचुरल बायो-इकोनॉमी मॉडल से बदल रही वनवासी महिलाओं का जीवन

लखनऊ । जंगल अब सिर्फ आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि वनवासी महिलाओं की आर्थिक आजादी की नई पहचान बन रहा है। योगी सरकार के नेचुरल बायो-इकोनॉमी मॉडल ने स्थानीय संसाधनों को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलकर वन क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार और सम्मान के नए रास्ते खोल दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए महिलाएं अब बकरी के दूध के साथ नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन और मोरिंगा जैसे प्राकृतिक अवयवों से हर्बल साबुन तैयार कर रही हैं, जो स्थानीय बाजार से निकलकर दूर-दराज के ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश का यह मॉडल जंगल से बाजार की अवधारणा को जमीन पर उतार रहा है। इसका सबसे सफल उदाहरण सोनभद्र जिले के विकास खंड रॉबर्ट्सगंज के ग्राम साजौर का बजरंगबली स्वयं सहायता समूह है। यहां की महिलाएं बकरी के दूध से तैयार हर्बल साबुन बनाकर न केवल अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं।बजरंगबली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 से अधिक महिलाएं नियमित रूप से हर्बल साबुन का उत्पादन करती हैं। समूह के जरिए महिलाएं हर महीने 50 से 60 हजार रुपये तक के उत्पाद बेच रही हैं। इससे प्रत्येक महिला को 8 से 10 हजार रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त आय हो रही है। यह आय उनके परिवार की आर्थिक मजबूती के साथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर का आधार बन रही है।समूह द्वारा तैयार किए जा रहे साबुन में बकरी के दूध के साथ नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन और मोरिंगा जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। इन उत्पादों को त्वचा के लिए सुरक्षित और पोषक विकल्प के रूप में बाजार में पहचान मिल रही है। स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले ये उत्पाद प्राकृतिक जीवनशैली की बढ़ती मांग के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रहे हैं।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

पर्यटन मंत्री ने किया रूचि चौहान रचित काव्य संग्रह 'मन के मौसम' पुस्तक का विमोचन

लखनऊ । पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन भवन के सभागार में रूचि चौहान द्वारा रचित काव्य संग्रह 'मन के मौसम' पुस्तक का विमोचन करते हुए लेखिका को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि काव्य संग्रह में नारी मन की कोमल भावनाओं को कविता के माध्यम से बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया गया है। यह पुस्तक नारी समाज तथा आधी आबादी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मन के मौसम काव्य संग्रह में नारी हृदय की सूक्ष्म भावनाओं, विविध अनुभूतियों तथा मिलन, वियोग, त्रासदी, शोषण के अलावा अनछुए पहलुओं को भी सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है। लेखिका का शब्द चयन भी सराहनीय है। पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि ईश्वर ने नारी को सृजन की शक्ति दी है। नारी के बिना यह संसार अधूरा है। कभी मां, कभी बहन, कभी पत्नी के रूप में उसका रोल समाज को गतिमान बनाता है। इस अवसर पर पर्यटन विकास निगम के एमडी आशीष कुमार, अशोक सिंह, डॉ0 संग्राम सिंह के अलावा बड़ी संख्या में नाबार्ड परिवार के सदस्य, शिक्षक उपस्थित थे।

ग्रेटर नोएडा में होगा अंतर्राष्ट्रीय बायोएनर्जी एवं टेक एक्सपो

लखनऊ । उत्तर प्रदेश को बायोएनर्जी एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में बुधवार को इन्वेस्ट यूपी सभागार, लखनऊ में इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय स्टेकहोल्डर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की।

लाठी लेकर निकले कांग्रेसी, पुलिस ने बैरिकेडिंग पर चढ़े कार्यकर्ताओं को धक्का दिया

लखनऊ । राजधानी लखनऊ में बुधवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से लाठी लेकर 5-कालिदास मार्ग की ओर कूच किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने तीन रास्तों पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों ने पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी। करीब 100 मीटर तक आगे बढ़ गए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़े पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धक्का देकर गिरा दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पगड़ी बांधकर बैरिकेडिंग के पास धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा। दरअसल, मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम आवास के पास धरना-प्रदर्शन किया था। इसके जवाब में भाजपा ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। इसके जवाब में कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में बैठक की। उसमें भाजपा को जवाब में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।

'जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान' को मिलेगा नया बल, कौशल प्रशिक्षण के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान' के तहत चिन्हित लाभार्थियों को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योगों और रोजगार बाजार की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी मिल सकें।उन्होंने कहा कि यह पहल 'जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान' को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आय बढ़ाने, उनकी आजीविका सुदृढ़ करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।राज्यमंत्री ने बताया कि शासनादेश के अनुसार यह धनराशि अनुदान संख्या-69 के अंतर्गत श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित मद से स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का उपयोग अभियान के तहत चिन्हित एवं आच्छादित लाभार्थियों को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में किया जाएगा।

पशुधन एवं दुग्ध विकास ने बरेली से खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान के आठवें चरण का शुभारम्भ किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज विकास भवन, बरेली में खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) रोग नियंत्रण कार्यक्रम के आठवें चरण के अंतर्गत निःशुल्क टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर टीकाकरण जागरूकता एवं अभियान से संबंधित वाहनों को रवाना किया, जो जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर पशुपालकों को जागरूक करेंगे तथा पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। खुरपका-मुहपका टीकाकरण अभियान का आठवां चरण 22 जुलाई, 2026 से 08 सितम्बर, 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। पशुओं को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खुरपका-मुंहपका अत्यंत संक्रामक रोग है, जिससे प्रभावित पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, प्रत्येक पात्र पशु का समय पर टीकाकरण कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को पूरी गंभीरता, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ संचालित करते हुए शत-प्रतिशत पात्र पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता वाहनों के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर पशुपालकों को टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि कोई भी पशु टीकाकरण से वंचित न रहे।

बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही जान सकते हैं,सपा मुख्यालय के बाहर लगीं होर्डिंग्स, बीजेपी को बताया युवा विरोधी

लखनऊ । दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार को राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अखिलेश यादव एवं सांसद डिंपल यादव के समर्थन में बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए। पार्टी कार्यालय के बाहर सुबह से ही समर्थकों की आवाजाही बढ़ी रही और पूरे परिसर में समर्थन के संदेश वाले बैनर लगाए गए। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों के जरिए अखिलेश यादव के प्रति एकजुटता दिखाई। पोस्टरों में पार्टी नेतृत्व के समर्थन और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया गया। नेताओं का कहना है कि दिल्ली में हुई कार्रवाई लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और पार्टी इसका राजनीतिक व लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी। अखिलेश यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यह प्रदर्शन संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और नीट-यूजी 2026 के कथित पेपर लीक मामले को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। विपक्षी दलों ने प्रदर्शन के दौरान नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गंभीर चूक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है। दिल्ली की घटना के बाद लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार कार्यालय पहुंचते रहे। समर्थकों ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव के समर्थन में नारे लगाए और पोस्टर अभियान चलाकर पार्टी नेतृत्व के साथ एकजुटता का संदेश दिया। सपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं, राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर और होर्डिंग को सपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

संसद छोड़ सड़क पर प्रदर्शन क्यों, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया: केशव मौर्य

कोई भी विषय है उसकी चर्चा संसद में होती है
संसद का सत्र चल रहा हो, तब सड़क पर इस प्रकार के उपद्रव व धरने-प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ । उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया और आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता करने का प्रयास है। उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी का जो कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर धरना था। वह गैर-जिम्मेदाराना था। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास था।केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलकर आए और नीट पर चर्चा कराने की सहमति दी। उसके बाद भी धरने पर बैठे रहना एक तरह से पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ाने के प्रयास जैसा था। भाजपा नेता ने कहा, एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। वह अराजकता पर उतारू है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने पर उतारू है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एंड कंपनी, ये सारे लोग माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं। श्री मौर्य ने कहा कि कोई भी विषय है उसकी चर्चा संसद में होती है। जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब सड़क पर इस प्रकार के उपद्रव व धरने-प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, अगर उनके पास मुद्दे हैं, तो उन्हें संसद में उठाना चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीति में इस तरह के सड़क पर विरोध-प्रदर्शन को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

भाजपा का कांग्रेस मुख्यालय तक कूच

लखनऊ । दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास और जंतर-मंतर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित हंगामे और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बुधवार को बीजेपी ने लखनऊ में भी मोर्चा खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटनाक्रम को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। दोपहर करीब एक बजे वीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पैदल मार्च की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने किया। पूरे मार्च के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।कार्यकर्ताओं ने वीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस मुख्यालय, मॉल एवेन्यू की ओर पैदल कूच किया। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारेबाजी होती रही। सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लिखे थे। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुरादाबाद के नारे भी लगाए और दिल्ली की घटना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।प्रदर्शन के दौरान लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल भी मौके पर मौजूद रहीं। उन्होंने कांग्रेस के कृत्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी को अपनी हरकतों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली की घटना को अनुशासनहीनता करार दिया और कहा कि इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है।

भारत तेजी से एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा : डॉ.बी.एस.राजपूत

लखनऊ। भारत में लाइफस्टाइल डिजीज और नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज का लगातार बढ़ता बोझ देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभर रहा है। विशेषज्ञों ने इन बीमारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, अर्ली डायग्नोसिस, मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट तथा एविडेंस-बेस्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन एवं सेल्युलर थेरपी की आवश्यकता पर बल दिया। इन्हीं विषयों पर सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान एवं ज्ञान मंच के संयुक्त तत्वावधान में आज होटल फॉर्च्यून बीबीडी में आयोजित स्पार्क हेल्थ डायलॉग में देश के वरिष्ठ चिकित्सक और स्टेम सेल शोधकर्ता डॉ बी एस राजपूत ने दीर्घकालिक बीमारियों और मरीजों की देखभाल में एडवांस्ड थैरेपीज की संभावित भूमिका पर गंभीर चर्चा की। डॉ. बी.एस. राजपूत वरिष्ठ चिकित्सक, स्टेम सेल थेरेपी, सेलुलर थेरेपी विशेषज्ञ एवं रिजेनेरेटिव मेडिसिन ने कहा कि भारत तेजी से एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अब संक्रामक रोगों की तुलना में क्रॉनिक डिजीज, डिजेनेरेटिव डिजीज और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अधिक बड़ी चुनौती बन रही हैं। उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बढ़ता मोटापा, असंतुलित खान-पान और औसत आयु में वृद्धि जैसी परिस्थितियां देश में क्रॉनिक बीमारियों के मामलों में तेजी से वृद्धि कर रही हैं। डॉ. राजपूत ने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य डिजेनेरेटिव मस्कुलोस्केलेटल डिस्ऑर्डर पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में करीब 18 करोड़ लोग विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस से प्रभावित हैं। वहीं 30 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 15 प्रतिशत वयस्कों में नी ऑस्टियो आर्थराइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में इसकी व्यापकता लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। न्यूरोलॉजिकल रीहैबिलिटेशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख नए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मामले सामने आते हैं, जिनमें लगभग आधे सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं, कृषि कार्यों से होने वाली चोटों तथा समय पर ट्रॉमा केयरकी सीमित उपलब्धता के कारण दीर्घकालिक पुनर्वास सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है।उन्होंने ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तथा एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जैसी दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का भी उल्लेख किया।स्टेम सेल थेरेपी, सेलुलर थेरेपी और रिजेनेरेटिव मेडिसिन पर चर्चा करते हुए डॉ. राजपूत ने स्पष्ट किया कि ये उभरती हुई चिकित्सा पद्धतियां पारंपरिक उपचार का विकल्प नहीं, बल्कि चयनित मरीजों के लिए एक अतिरिक्त चिकित्सीय विकल्प हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नी ऑस्टियो आर्थराइटिस, स्पोर्ट्स इंजरी, कार्टिलेज रिजेनेरेशन, टेंडन एवं लिगामेंट रिपेयर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डायबिटिक वाउंड हीलिंग तथा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इन उपचारों का क्लीनिकल मूल्यांकन किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि स्टेम सेल थेरेपी और सेलुलर थेरेपी बायोमेडिकल साइंस के तेजी से विकसित होते क्षेत्र हैं, जिनमें उपचार की व्यापक संभावनाएं हैं। लेकिन इनका उपयोग हमेशा मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण, नैतिक मानकों, नियामकीय निगरानी और मरीजों के सावधानीपूर्वक चयन के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान के प्रोग्राम डायरेक्टर राकेश मिश्र ने कहा स्पार्क हेल्थ डायलॉग का उद्देश्य चिकित्सकों, बायोमेडिकल शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, स्वास्थ्य संचार विशेषज्ञों और समाज के बीच एक सशक्त एवं विश्वसनीय संवाद का मंच तैयार करना है।

भूजल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार को जनआंदोलन बनाने का आह्वान

लखनऊ(आरएनएस)। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश की ओर से सोमवार को 'भूजल संरक्षण एवं नदी पुनरुद्धार' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, नदी पुनर्जीवन और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना था।कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर सिंह, विशेष सचिव एवं निदेशक भूगर्भ जल विभाग राजेश प्रजापति तथा जल संरक्षण विशेषज्ञ एवं पूर्व आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विनोद तारे ने दीप प्रज्ज्वलित एवं जल कलश पूजन कर किया।इस अवसर पर गंगा अवतरण पर आधारित सांस्कृतिक नृत्य-नाटिका का मंचन किया गया। साथ ही राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया तथा 'गंगा ज्ञान चक्र' पहल का परिचय और प्रस्तुतीकरण भी किया गया।अपने संबोधन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए सभी प्रतिभागियों से जल बचाने और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों से जल संरक्षण के लिए 'जल एंबेसडर' के रूप में कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के बिना जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता।उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वर्तमान समय में जल उपलब्धता की स्थिति, जल संकट की चुनौतियों और इसके संरक्षण के व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला।कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 'भागीरथ सम्मान' से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा प्रत्येक नागरिक को जल स्रोतों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।दोपहर में आयोजित तकनीकी सत्र में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों ने भूजल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन, जल प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक सहभागिता पर अपने विचार साझा किए। इस सत्र में मुंबई के भूषण गुप्ता, डॉ. आडुरी कैटना हर्नांडिज, प्रो. विनोद तारे, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी के प्रभात सिंह, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वेंकटेश वट्टा तथा सिंचाई विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ अशोक कुमार सिंह ने विषय विशेषज्ञ के रूप में अपने सुझाव प्रस्तुत किए।विशेषज्ञों ने कहा कि लगातार गिरते भूजल स्तर, नदियों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होगा, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी से ही इस दिशा में स्थायी सफलता प्राप्त की जा सकती है।समापन सत्र में संगोष्ठी के दौरान प्राप्त सुझावों और संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा उन्हें भविष्य की कार्ययोजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।